भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3818**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते

3818. श्री पुट्टा महेश कुमार:

श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ प्रस्तावित, वार्ताधीन और वर्तमान में लागू सभी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की देश-वार सूची का ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से वे समझौते कौन से हैं जो प्रौद्योगिकी - गहन क्षेत्रों, महत्वपूर्ण खनिजों, उन्नत विनिर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों में नए निवेश को सुगम बनाते हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एफटीए से प्राप्त व्यापार मूल्य, निवेश आवक और रोजगार सृजन का विशेष रूप से वर्तमान में उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित निवेश को आकर्षित करने और साझेदार देशों के साथ एफटीए का विस्तार करने के उद्देश्य से डिजिटल व्यापार ढांचे, डेटा सुरक्षा और नियामक निश्चितता को मजबूत करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) भारत के साथ प्रस्तावित, वार्ता के तहत और वर्तमान में लागू मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की एक सूची अनुलग्नक में दी गई है। भारत के लागू मुक्त व्यापार समझौतों का विवरण और मुख्य विशेषताएं https://www.commerce.gov.in/#/international-trade/trade-agreements. पर प्राप्त की जा सकती हैं। हाल के एफटीए की संक्षिप्त विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए): भारत ने अपने निर्यात के लिए 100% शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच हासिल की है, जो ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों को कवर करता है, जो भारत के निर्यात मूल्य का 99.38% है।

- भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) यूके को किए जाने वाले भारत के लगभग 99% निर्यातों तक शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करता है। सभी शून्य-शुल्क रियायतें समझौता लागू होने के साथ ही लागू हो जाती हैं। भारत के प्रमुख निर्यात- कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूते, जैविक रसायन, कारीगर उत्पाद और सिरेमिक जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे उच्च मूल्य वाले सामानों ने यूके में शून्य-शुल्क पहुंच हासिल की है।

- भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए): भारत ने ईएफटीए से 92.2% टैरिफ लाइनों (भारत के निर्यात का 99.6%) को कवर करते हुए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता प्राप्त की है, जिसमें 100% गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता: एफटीए में खाद्य, कृषि और समुद्री उत्पादों सहित भारत के सभी निर्यात 1 जनवरी 2026 से शून्य-शुल्क बाजार पहुंच के लिए पात्र हैं।

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए): भारत ने भारत के 99% निर्यात को कवर करने वाली संयुक्त अरब अमीरात टैरिफ लाइनों के 97% पर शुल्क मुक्त और अधिमान्य बाजार पहुंच हासिल की है, जिसमें 80% से अधिक टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्त किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता पूरी कर ली गई है। इसकी संक्षिप्त विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भारत-न्यूजीलैंड एफटीए: न्यूजीलैंड समझौते के लागू होने पर कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों, समुद्री उत्पादों, डेयरी उत्पादों और अन्य ग्रामीण आजीविका-आधारित उत्पादों सहित सभी टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और वर्तमान में यह अनुसमर्थन के अधीन है।

- भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) एफटीए: 96.8% टैरिफ लाइनों पर अधिमान्य बाजार पहुंच जो भारत के निर्यातों के 99.5% को कवर करती है। समझौते के लागू होने पर यूरोपीय संघ को निर्यात का 90.7% (व्यापार मूल्य के अनुसार) शुल्क मुक्त हो जाएगा। यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के बाद लागू होगा। हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की प्रक्रिया दोनों पक्षों द्वारा आपसी परामर्श से आगे बढ़ाई जाएगी।

एफटीए पर व्यापक, संतुलित, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम देने के प्रयास के साथ वार्ता की जाती है। यह व्यापारिक भागीदार देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए एक तरजीही, स्थिर और पूर्वानुमानित व्यापार इकोसिस्टम को भी सक्षम बनाता है। इस संरचित दृष्टिकोण के अलावा, कार्यान्वयन के बाद, सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और यदि कोई चुनौती हो, तो उसका समाधान करने के माध्यम से एफटीए का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। सांकेतिक रूप से, हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए में, मार्च 2024 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ हस्ताक्षरित और अक्टूबर 2025 में लागू किए गए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) में 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता शामिल है। इसी तरह, अप्रैल, 2026 में हस्ताक्षरित भारत-न्यूजीलैंड एफटीए अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।

भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 677 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 863 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख एफटीए भागीदार देशों और व्यापार ब्लॉकों को व्यापारिक निर्यात 179.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 40.5 प्रतिशत है। हाल ही में एफटीए भागीदार को व्यापारिक निर्यात से भी महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि का संकेत मिला है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सीईपीए कार्यान्वयन से पहले) से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 37.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ईसीटीए के कार्यान्वयन के बाद ऑस्ट्रेलिया को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी तरह, ईएफटीए देशों को निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(ग) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 एक मजबूत डेटा गोपनीयता ढांचा स्थापित करता है। यह व्यक्तिगत डेटा के वैध प्रसंस्करण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डेटा न्यासियों पर संबंधित दायित्व रखता है। यह अधिनियम नागरिकों को डेटा न्यासियों के खिलाफ लागू करने योग्य अधिकार देकर सशक्त बनाता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी)

नियम 2025 को सीमा पार हस्तांतरण सहित व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह ढांचा केंद्र सरकार को अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें जहां आवश्यक हो व्यक्तिगत डेटा की कुछ श्रेणियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध शामिल है।

सरकार विश्व-भर के संभावित देशों के साथ डिजिटल व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में डिजिटल व्यापार को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से डिजिटल व्यापार पर एक समर्पित अध्याय शामिल है।

*****

11.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3818 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

चल रही एफटीए वार्ता

चल रही एफटीए वार्ताएं

1. भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
2. भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
3. भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (भारत-ईएईयू) एफटीए
4. भारत-इज़राइल एफटीए
5. भारत-पेरू एफटीए
6. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
7. भारत-मालदीव एफटीए

समीक्षा/उच्चस्तरीय वार्ता के अधीन एफटीए

1. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) की समीक्षा
2. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) समीक्षा
3. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
4. भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ईटीसीए)

वार्ता के लिए हस्ताक्षरित टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (टीओआर)

1. भारत – फिलीपींस पीटीए
2. भारत – खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)

-

भारत के लागू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

-

हाल ही के एफटीए

क्रम संख्या	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल, 2021

2	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड-ऑस ईसीटीए)	2 अप्रैल, 2022	29 दिसंबर 2022
4	भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीईपीए) (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड)	10 मार्च 2024	01 अक्टूबर 2025
5	भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई 2025	15 जुलाई 2026
6	भारत – ओमान सीईपीए	18 दिसंबर 2025	01 जून 2026
7	भारत-न्यूजीलैंड एफटीए	27 अप्रैल 2026	अनुसमर्थन प्रक्रिया के अंतर्गत

नोट: यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता 27 जनवरी 2026 को संपन्न हो गई है। इसके अलावा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने 7 फरवरी, 2026 को घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) और भारत पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार के संबंध में एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा पर पहुंच गए हैं। वार्ता चल रही है।

अन्य एफटीए

क्रम संख्या	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता	28 दिसंबर , 1998	1 मार्च , 2000
2	एसएएफटीए पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान)	4 जनवरी , 2004	1 जनवरी , 2006 (टैरिफ रियायतें 1 जुलाई, 2006 से लागू)
3	भारत नेपाल व्यापार संधि	27 अक्टूबर , 2009	इस संधि को एक बार में सात साल की अवधि के लिए स्वचालित रूप से बढ़ाया जाएगा, जब तक कि दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को संधि को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में तीन महीने पहले लिखित सूचना नहीं देता है।
4	भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौता	17 जनवरी , 1972	पारस्परिक रूप से सहमत संशोधनों के साथ समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता है। 29 जुलाई, 2006 का समझौता 10 वर्षों के लिए वैध था। आपसी सहमति से, वैधता को एक वर्ष की अवधि या प्रस्तावित नए समझौते के लागू होने तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। इस नवीकृत समझौते पर 12.11.2016 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 29 जुलाई, 2017 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू हुआ है।

5	भारत - थाईलैंड एफटीए - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस)	9 अक्टूबर , 2003	1 सितंबर , 2004
6	भारत - सिंगापुर सीईसीए	29 जून , 2005	1 अगस्त , 2005
7	भारत - आसियान-सीईसीए - वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार और निवेश समझौता (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	वस्तु के लिए 13 अगस्त, 2009 और सेवाओं और निवेश के लिए नवंबर 2014	वस्तु • भारत और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के संबंध में जनवरी 1 2010 • भारत और वियतनाम के संबंध में 2010 जून 1 • भारत और म्यांमार के संबंध में 2010 सितम्बर 1 • भारत और इंडोनेशिया के संबंध में 2010 अक्टूबर 1 • भारत और ब्रुनेई के संबंध में 1 2010 नवंबर • भारत और लाओस के संबंध में 2011 जनवरी 24 • भारत और फिलीपींस के संबंध में 2011 जून 1 • भारत और कंबोडिया के संबंध में अगस्त 1, 2011 सेवाएँ और निवेश 1 जुलाई , 2015
8	भारत - दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त , 2009	1 जनवरी , 2010
9	भारत - जापान सीईपीए	16 फरवरी , 2011	1 अगस्त , 2011
10	भारत - मलेशिया सीईसीए	18 फरवरी , 2011	1 जुलाई , 2011

****